

INFERENCE

निर्देशः (प्रश्न 1-5)

नीचे एक परिच्छेद दिया गया है और उसके नीचे उस परिच्छेद में दिये गये तथ्यों के आधार पर निकाले जा सकने वाले कुछ संभावित अनुमान दिये गये हैं। आप हर एक अनुमान की परिच्छेद के संदर्भ में अलग-अलग परीक्षा कर उसकी सत्यता की मात्रा निश्चित कीजिये-

उत्तर (1) दीजिये यदि अनुमान “निश्चित रूप से सत्य” है अर्थात् वह दिये गये तथ्यों को उचित रूप से अनुसरण करता है।

उत्तर (2) दीजिये यदि “संभवतः सत्य है” यद्यपि दिये गये तथ्यों के संदर्भ में “निश्चित रूप से सत्य” नहीं है।

उत्तर (3) दीजिये यदि “दिये हुये तथ्य काफी नहीं हैं” अर्थात् दिये हुए तथ्यों से अनुमान सत्य है अथवा असत्य यह आप नहीं कह सकते हैं।

उत्तर (4) दीजिये यदि “संभवतः असत्य” है यद्यपि दिये गये तथ्यों के संदर्भ में “निश्चित रूप से असत्य” नहीं है।

उत्तर (5) यदि अनुमान “निश्चित रूप से असत्य” है यद्यपि दिये गये तथ्यों के संदर्भ में “निश्चित रूप से असत्य” नहीं है।

I. घरेलू स्टील उद्योग चुनौतीपूर्ण समय से गुजर रहा है। कच्चे माल की कीमतें पुरजोश बढ़ रही हैं और सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए अंतिम उत्पाद (स्टील) की कीमतों की उच्चतम सीमा नियंत्रित रखने के प्रयास कर रही हैं। उल्लेखनीय है कि स्टील की कीमतें जिनका WPI में लगभग 3.63% का योगदान है, उनके नियंत्रण के लिए सरकार ने पिछले छह महीने में विशेष रूप से कई कदम उठाए हैं। अब तीन महीने तक कीमतों का यथावत् रखने के बाद अब फिर से सरकार और स्टील निर्माताओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया है। स्टील निर्माता शीघ्र कीमतें बढ़ाने वाले हैं इस पूर्वाभास के साथ सरकार प्रतिकार स्वरूप स्टील उत्पादों की कीमतों से लगभग 30% अधिक हैं अतः स्टील उत्पादों की कीमतों के दायरे को नियंत्रित करना, स्टील उद्योग के प्रति अनुचित व्यवहार करने के समान होगा। 2008 में घरेलू बाजारों में हुई केवल 20% वृद्धि की तुलना में वैश्विक कीमतें 50%-60% बढ़ी हैं।

- पश्चिमी दुनिया के कुछ देशों ने अपने घरेलू बाजारों में स्टील उत्पादों की कीमतों के दायरे को निर्धारित किया है।
- स्टील की कीमतों के दायरे को निर्धारित करने का सरकार का कदम भारत के स्टील विनिर्माण यूनिटों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
- स्टील की कीमतें भारत के थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का एक अभिन्न अंग है।
- हाल ही के महीनों में भारत की मुद्रास्फीति की दर में कमी हुई है।

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्टील की कीमतों में वृद्धि घरेलू बाजार से बहुत कम हुई थी।

निर्देशः (प्रश्न 6-15)

नीचे एक परिच्छेद दिया गया है और उसके नीचे उस परिच्छेद में दिये गये तथ्यों के आधार पर निकाले जा सकने वाले कुछ संभावित अनुमान दिये गये हैं। आप हर एक अनुमान की परिच्छेद के संदर्भ में अलग-अलग परीक्षा कर उसकी सत्यता की मात्रा निश्चित कीजिये-

उत्तर (1) दीजिये यदि अनुमान “निश्चित रूप से सत्य” है अर्थात् वह दिये गये तथ्यों को उचित रूप से अनुसरण करता है।

उत्तर (2) दीजिये यदि अनुमान “संभवतः सत्य है” यद्यपि दिये गये तथ्यों के संदर्भ में “निश्चित रूप से सत्य” नहीं है।

उत्तर (3) दीजिये यदि “डाटा अपर्याप्त है” अर्थात् दिये हुए तथ्यों से अनुमान सत्य है अथवा असत्य यह आप नहीं कह सकते हैं।

उत्तर (4) दीजिये यदि अनुमान “संभवतः असत्य” है यद्यपि दिये गये तथ्यों के संदर्भ में “निश्चित रूप से असत्य” नहीं है।

उत्तर (5) यदि अनुमान “निश्चित रूप से असत्य” है अर्थात् दिये गये तथ्यों का संभवतः अनुसरण नहीं करता है अथवा वह दिये गये तथ्यों के विपरीत जाता है।

- देश यदि अच्छा विदेशी निवेश आकर्षित करना चाहता है तो विदेशी निवेशकों के पथ में विनियमनों द्वारा लादी गई बाधाएं दूर की जानी चाहिए। विशेषतः तब जब कि विदेशी संस्थागत निवेशक भारतीय स्थिति से बहुत प्रभावित प्रतीत नहीं होते हैं। विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ 1990 के शुरूआती महीनों के स्तर तक गिरने के जोखिम का सामना नहीं कर रही है। फिर भी, देश को केवल संविभाग अंतर्वाह या हॉट मर्नी के बजाय अधिक दीघावधि निवेश आकर्षित करनेके लिए बातावरण का निर्माण करना चाहिए। 1998 में जारी विनियम के डाइल्ट्यूटेड वर्शन की यह आवश्यकता कि 2005 से पहले भारत में स्थापित JVs वाले विदेशी भागीदारों को दूसरा समान उद्यम स्थापित करने के लिए देशी भागीदार से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए, के दुरुपयोग की संभावना से पहले, विदेशी भागीदार को सरकार से भी पुर्वानुमति प्राप्त करनी चाहिए।

- वर्तमान परिदृश्य में विदेशी निवेशक भारत में दीर्घावधि परियोजनाओं में निवेश करने के लिए उत्सुक हैं।

- एशियाई महाद्वीप के बहुत से देशों में विदेशी निवेशकों के लिए अनुकूल दिशानिर्देश हैं।

- 1990 से आरंभ में भारत की विदेशी मुद्रा आरक्षितियाँ वर्तमान स्तर से बहुत कम थीं।



9. प्रमुख क्षेत्रों में विदेशी निवेश को अनुमति देने के लिए भारत को अपने मानदण्ड कड़े करने चाहिए।

10. भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मुख्यतः अल्पावधि है।

III. तात्कालिक चुनौती खाद्य के मोर्चे पर है उत्पादन में कमी का आपूर्ति पर और इसलिए कीमतों पर प्रभाव पड़ने दिया गया है। सरकार सिंचाई में निवेश पर ध्यान केंद्रित करने और कृषि विस्तार प्रणाली के पुनरुज्जीवन तक ही योजना बना रही है। संभवतः जरूरत हरित क्रांति की रणनीति की नई खुराक की है। ऐसा लगता है कि हरित क्रांति की रणनीति कीमतों के धराशायी होने के जोखिम को राज्य द्वारा उठाए जाने पर आधिकारित थी। यदि खुला बाजार उपज को न ले पाए तो राज्य किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य और खरीद की गारंटी देता था। तब किसान बैंकों से उधार ले पाते थे, हरित क्रांति प्रौद्योगिकी अर्जित कर पाते थे और जितना हो सके उतनी पैदावार कर सकते थे। जब तक खाद्य की कमी थी, खाद्य सब्सिडी पर दबाव सहनीय था। फिर खुले बाजार में कीमतों का रूझान सरकारी खरीद मूल्य से ऊपर रहने का होता था। लेकिन खाद्य की अधिकता से स्थिति बदल गई है। स्थिति सिर्फ सब्सिडी के परिणाम के कारण असहनीय नहीं था। यह अक्षम भी थी। इसका अर्थ था कि किसान केवल सरकार द्वारा निश्चित किए जाने वाले मूल्य के आधार पर फसल उगाने के लिए प्रेरित हो रहे थे न कि किसी वास्तविक मांग से। इस परिस्थिति में सरकार खरीद-मूल्य को उस गति से बढ़ाए जाने की अनिच्छुक थी जो शुरू के वर्षों में एक मानदण्ड हुआ करता था।

11. सरकार हरित क्रांति की रणनीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने की योजना बना रही है।

12. अब सरकार किसानों को सब्सिडी देने की स्थिति में नहीं है।

13. चूंकि खुले बाजार में कीमतें नीचे हैं, फसलों की खरीद का सारा बोझ सरकार पर है।

14. किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की मात्रा से मांग बहुत अधिक है।

15. किसान अपनी सुविधा के अनुसार फसल उगाने को प्रवृत्त होते हैं, मांग के अनुसार नहीं।

निर्देश: (प्रश्न 16–20)

नीचे एक परिच्छेद दिया गया है और उसके नीचे उस परिच्छेद में दिये गये तथ्यों के आधार पर निकाले जा सकने वाले कुछ संभावित अनुमान दिये गये हैं। आप हर एक अनुमान की परिच्छेद के संदर्भ

Inference

- | | | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1. (d) | 2. (b) | 3. (a) | 4. (b) | 5. (e) | 6. (b) | 7. (c) |
| 8. (a) | 9. (b) | 10. (d) | 11. (b) | 12. (d) | 13. (a) | 14. (e) |
| 15. (a) | 16. (b) | 17. (b) | 18. (d) | 19. (a) | 20. (e) | |

में अलग-अलग परीक्षा कर उसकी सत्यता या असत्यता की मात्रा निश्चित कीजिये-

उत्तर (1) दीजिये यदि अनुमान निश्चित रूप से सत्य है अर्थात् वह दिये गये तथ्यों को उचित रूप से अनुसरण करता है।

उत्तर (2) दीजिये यदि अनुमान प्रायः सत्य है यद्यपि दिये गये तथ्यों के संदर्भ में निश्चित रूप से सत्य नहीं है।

उत्तर (3) दीजिये यदि दिये गये तथ्य काफी नहीं है। अर्थात् दिये हुए तथ्यों से अनुमान सत्य है अथवा असत्य यह आप नहीं कह सकते हैं।

उत्तर (4) दीजिये यदि प्रायः असत्य है यद्यपि दिये गये तथ्यों के संदर्भ में निश्चित रूप से असत्य नहीं है।

उत्तर (5) यदि अनुमान निश्चित रूप से असत्य है अर्थात् दिये गये तथ्यों का संभवतः अनुसरण नहीं करता है अथवा वह दिये गये तथ्यों के विपरीत जाता है।

III. आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण ने भारतीय उद्योग, विशेषकर सेवा क्षेत्र पर कम कीमत पर और तेज गति से गुणवत्ताप्रक उत्पाद और सेवाएं उपलब्ध करवाने का दबाव बना दिया है। संस्थाओं को विदेशों के असमान भागीदारों से प्रतिस्पर्धा करनी है। सब अच्छी तरह जानते हैं कि भारत जैसे विकासशील देश प्रौद्योगिकीय दृष्टि से और दूसरे कई क्षेत्रों में दूसरे देशों से पीछे हैं, हालांकि उनमें से कुछ एक, खासकर भारत, विशाल वैज्ञानिक और तकनीक श्रमशक्ति का दम भरता है। इसके अलावा, यदि एक उद्यमी या उद्योगपति को अपना बहुत सा समय, धन और ऊर्जा अननुमेय सेवाओं से निवटने और स्थानीय नौकरशाही से बातचीत में खर्च करनी पड़े, तो इसका व्यवसाय पर अत्यधिक दुष्प्रभाव पड़ सकता है।

16. भारत के सिवा अन्य कोई प्रगतिशील देश यह दावा नहीं करता है कि उनके पास उच्च प्रशिक्षण-प्राप्त तकनीकी श्रमशक्ति है।

17. घरेलू कंपनियों की तुलना में विदेशी कंपनियां बिना देरी के गुणवत्ताप्रक सेवा उपलब्ध कराने की दृष्टि से ज्यादा लैस है।

18. सरकारी औपचारिकताएं भारत के सिवा लगभग सभी देशों में कम बाधक हैं।

19. आर्थिक उदारीकरण से पहले भारीतय सेवा उद्योग ज्यादा इत्मीनान से था।

20. प्रौद्योगिकीय विकास की दृष्टि से भारत वर्तमान में कुछ हद तक विकसित देशों के समकक्ष है।

